

Finance Minister to the shipping industry and the tea estates. The shipping industry, as we all know, as also the tea industry, are our very good foreign exchange earners and as such any concessions granted to them will be in the interests of the country itself and its finances.

I am indeed happy to know from the day before yesterday's newspaper that my State of U.P., during the next Five Year Plan, is to get fifteen new industrial units in the public sector.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : You should end with the happy note that fifteen industries are coming up.

PANDIT S. S. N. TANKHA : This is indeed good news for U.P. which had been utterly neglected in the matter of setting up of new industries during the last two plans and in the current Third Five Year Plan also. I do hope that the projected industries will be set up and will not be postponed. In this connection may I draw the attention of the Finance Minister that for the adequate development of a large State like U.P. which contains almost one-sixth of the population of India, it is absolutely necessary for it to have an adequate supply of electricity, but while the State has a surplus of power supply, it is still very short of transmission lines for which I funds from the Government of India are in urgent need. I hope the Finance Minister will give this matter his urgent and sympathetic consideration.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE APPROPRIATION BILL, 1966

SECRETARY : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha :

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Appropriation Bill, 1966, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 1966.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE BUDGET (GENERAL). 1966-67—GENERAL DISCUSSION— *continued*

श्री जगन्नाथ प्रसाद (राजस्थान) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बजट के सम्बन्ध में लगभग सभी मदों पर प्रकाश डाला है और स्वयं वित्त मंत्री महोदय ने देश के सामने जो विभिन्न समस्याएँ हैं उन पर प्रकाश डालते हुये अपने कर प्रस्तावों को रखा है। उन्होंने बजट का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना, हमारे यहां के निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना बताया है। इन्हीं मदों को ध्यान में रख कर मैं भी अपने कुछ सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में कुछ और समस्याओं की ओर हमारा ध्यान दिलाया जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में अपर्याप्त कार्य पूँजी, बाजार की सुस्ती, शोधन-सन्तुलन पर दबाव और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि। इसके साथ-साथ हमारी पैदावार पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वह भी हमारे ध्यान में है। वित्त मंत्री जी ने इन सब बातों को ध्यान में रख कर देश के सामने एक बजट पेश किया जिसमें उन्होंने कुछ कमी की चर्चा की और पूँजी खाते में लगभग 112 करोड़ रुपये की वास्तविक कमी के कारण भी बताया और उन कारणों में उन्होंने पहला कारण बताया, विदेशी सहायता की कमी और दूसरा कारण बताया राज्यों को दी गई कुछ ऋण सहायता जो कि लगभग 100 करोड़ की हो जाती है।

श्रीमन्, ये सब बातें तो हमारे सामने बराबर आती हैं और इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर जितने भी वित्त मंत्री हैं उन्होंने यहां पर बजट पेश किये हैं और उन सिद्धान्तों के आधार पर कुछ कर लगाये हैं। इस बार भी